दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 21 अक्टूबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 26

महत्वपूर्ण एवं खास

मेरठ में पत्नी की गला काटकर हत्या, आरोपी पति फरार

मेरठ (आरएनएस)। यूपी के मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में चरित्र पर शक होने पर एक व्यक्ति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोपी के बेटे ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह को एक महिला की हत्या के संबंध में पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी (एसएचओ) जितेन्द्र कुमार ने कहा कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को एक मकान के अंदर से 55 वर्षीय सतलीव का शव मिला, जिसकी गर्दन किसी धारदार हथियार से कटी हुई थी। एसएचओ ने कहा कि मृतिका के बेटे वकार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एक प्राथमिक दर्ज की गई है, जिसमें मृतिका के पति इसरार को नामजद आरोपी बनाया गया है। एसएचओ ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वर्तमान में जांच जारी है। आरोपी को पकडऩे के लिए दो टीमों का गठन किया गया है।

खड़गे ने जम्मू-कश्मीर इकाई में किया फेरबदल, बनाई कार्यकारी समिति और 5 नए उपाध्यक्ष

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई में बड़ा फेरबदल करते हुए एक कार्यकारी समिति का गठन किया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता करण सिंह को सदस्य बनाया गया। कांग्रेस ने पांच वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 22 उपाध्यक्ष, 51 महासचिव, 62 सचिव और 21 जिला प्रमुखों की भी नियुक्ति की। पार्टी ने एक बयान में कहा कि खडग़े ने 22 सदस्यीय कार्यकारी समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें अनुभवी नेता करण सिंह और सैफुद्दीन सोज के साथ-साथ वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा और तारा चंद शामिल हैं। खडग़े ने पांच उपाध्यक्षों के नाम बताए, जिनमें मूला राम, जी.एन. मोंगा, बलवान सिंह, रविंदर शर्मा, और मोहम्मद अनवर भट शामिल हैं। रजनीश शर्मा को इकाई का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विकार रसूल वानी जेकेपीसीसी प्रमुख हैं।

प्रधानमंत्री का पार्टनर से 10 साल पुराना रिश्ता टूटा, कमेंट को लेकर आई दरार

रोम। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने पार्टनर जियाम्ब्रुनो से ब्रेकअप कर लिया है। उन्होंने आज घोषणा की कि वह लगभग एक दशक तक साथ रहने के बाद अपने पार्टनर से अलग होने जा रही हैं। मेलोनी की पार्टनर के साथ एक बेटी भी है। जियाम्ब्रुनो और मेलोनी की शादी नहीं हुई है। हालांकि, वे लंबे समय से रिश्ते में थे। उनकी एक सात साल की बेटी भी है। एक टेलीविजन चैनल पर ए क जानेमाने कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले जियाम्ब्रुनो अगस्त में उस समय आलोचनाओं से घिर गए थे, जब उन्होंने अपने शो में सुझाव दिया था कि महिलाएं बहुत अधिक शराब न पीकर दुष्कर्म से बच सकती हैं। इस पर मेलोनी ने कहा था कि उन्हें उनके पार्टनर की टिप्पणियों के आधार पर आंका नहीं जाना चाहिए और भविष्य में वह उनके व्यवहार के बारे में सवालों का जवाब नहीं देंगी।

चीन में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

बीजिंग। चीन के दक्षिणी हिस्सों में शुक्रवार को भारी बारिश के आसार है और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया किया गया है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अपराह्न दो बजे से शनिवार अपराह्न दो बजे तक गुआंग्शी और गुआंगडोंग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान हैं। इन क्षेत्रों में इस अधिकतम 80 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने स्थानीय सरकारों को प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व तैयारी कर लेने और यातायात प्रबंधन अधिकारियों को भारी बारिश से प्रभावित सडक़ों पर उचित यातायात नियंत्रण उपाय लागू करने की सलाह दी है। इसके अलावा, जोखिम वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को काटने और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का भी सुझाव दिया गया है।

पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल 'नमो भारत' के 17किमी लंबे पहले खंड का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहे।

कल से आम नागरिक इस ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का पहला चरण 17 किलोमीटर लंबा है। यानी अभी यात्री गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक यात्रा कर सकेंगे। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का ट्रेन किराया 50 रुपए रखा गया है। वहीं, प्रीमियम कोच के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे।

इस कॉरिडोर की लंबाई 82 किमी है, जिसमें से 14 किमी का हिस्सा दिल्ली में और 68 किमी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) एनसीआर में इस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसे दिल्ली मेट्रो की अलग-अलग लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा. ये अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे शहरों को भी दिल्ली से जोड़ेंगे.

180 KM की गति से चल सकती है नमो भारत

आरआरटीएस ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि, ये ट्रेनें पटरियों पर 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी. यह ट्रेन 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. 6 कोच वाली इस ट्रेन का लुक बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है. आरआरआरटीएस को उन यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो तेज गति और शांत तरीके से लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं.

पहले खंड में 5 स्टेशन

पहले खंड में रैपिड रेल साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच चलाई जाएगी. आरआरटीएस का प्राथमिक खंड देश की ऐसी पहली रेलवे प्रणाली है, जिसे 160 किमी प्रति घंटा की अधिकतम परिचालन गति पर पूरा सफर तय करने के लिए खोला जा रहा है. रैपिडएक्स, यात्रियों के लिए तेज़, सुरक्षित और आरामदायक रीजनल आवागमन सेवा सुनिश्चित करेगा. दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बहुकेंद्रित और संतुलित विकास को सक्षम कर, रोजगार, व्यवसाय और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा. सार्वजनिक परिवहन के इस सस्टेनेबल साधन से भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है.

महिलाएं संभालेंगी इन ट्रेनों की कमान

इन आधुनिक हाई स्पीड, हाई-फ्रीक्वेंसी रैपिडएक्स ट्रेनों के संचालन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इस खंड के परिचालन में महिला कर्मचारियों की भागीदारी पुरुष कर्मचारियों से अधिक होगी. प्राथमिक खंड में रैपिडएक्स ट्रेनों के संचालनों के लिए नियुक्त ट्रेन संचालकों में पुरुष संचालकों की तुलना में महिला संचालकों की संख्या अधिक है. इसके अलावा, स्टेशन कंट्रोल, प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ट्रेन अटेंडेंट आदि के रूप में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक पुल से गिरा- चार लोगों की मौत

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के झज्जर कोटली इलाके में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जीएमसी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है।

मृतकों में ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यह ट्रक श्रीनगर से राजस्थान की ओर जा रहा था। यह हादसा वीरवार और शुक्रवार की देर रात करीब ढाई बजे झज्जर कोटली इलाके में झज्जर पुल पर घटित हुआ है।

जानकारी के अनुसार कश्मीर से सेबों को लेकर जम्मू की ओर आ रहा ट्रक आरजे13जीबी-5654 झज्जर पुल पर पहले डिवाइडर के साथ टकराया और उसके बाद ट्रक लगभग अस्सी फीट नीचे नाले में जा गिरा। ट्रक में सेब लदे होने के कारण वह अधिक दबाव सह नहीं पाया और ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक में सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कॉलेजियम की ठंडे बस्ते में पड़ी सिफारिशों को 'बाहर निकालना होगा : सुको

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र के पास ठंडे बस्ते में पड़ी कोलेजियम की सिफारिशों को वहां से बाहर निकालना होगा। न्यायमूर्ति एस.के. कौल, सुधांशु धूलिया और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि पांच दोहराए गए नाम, पांच नए नाम और स्थानांतरण से संबंधित 11 फाइलें अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए केंद्र द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचनाएं एक सकारात्मक विकास है और केंद्र द्वारा दी गई इस दलील पर ध्यान दिया कि मामलों को सुलझाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने दो-तीन सप्ताह की मोहलत मांगी। विधि अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले को नवंबर 2023 के दूसरे सप्ताह में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। हालाँकि, इसने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चुनिंदा नामों को अधिसूचित करने से कॉलेजियम की सिफारिश में निहित वरिष्ठता के क्रम में गड़बड़ी होती है और परिणामस्वरूप मेधावी वकील अक्सर पीछे हट जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह कॉलेजियम की 70 लंबित सिफारिशों के मुद्दे पर अगले दो महीने तक नियमित अंतराल पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत के दबाव के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों से बड़ी संख्या में लंबित सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दी थीं। केंद्र ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न फाइलों को भी मंजूरी दे दी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को अधिसूचित करने में देरी करता है तो न्यायाधीशों की डीम्ड नियुक्ति नहीं हो सकती है।

इसने कहा था कि यह उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण के वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश की प्रकृति में निर्देश पारित नहीं कर सकता है। कई याचिकाओं में कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें भेजे जाने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है।

सफाई अभियान : रक्षा मंत्रालय ने विभागों में खाली की 92,850 वर्ग फुट जगह

❐ हासिल किया 55.43 करोड़ रुपए का राजस्व

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 18 अक्टूबर तक उनके विभिन्न विभागों में कुल 92,850 वर्ग फुट जगह खाली की गई है और 55.43 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राजस्व बेकार हो चुके वाहनों की नीलामी और अन्य स्क्रैप तथा अप्रचलित ओटीईएम के निपटान के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

रक्षा विभाग सहवर्ती स्वच्छता अभियान के साथ विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन चरण (02-31 अक्टूबर, 2023) के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। रक्षा विभाग ने पूरे भारत में कुल 3066 स्थानों की पहचान की थी, जहां लोक-केंद्रित भागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। ये स्थान विभिन्न संगठनों जैसे रक्षा लेखा महानियंत्रक, सीमा सडक़ संगठन, सैन्य अस्पताल, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, भारतीय तटरक्षक बल, सैनिक स्कूल, कैंटीन स्टोर विभाग और छावनियों से संबंधित हैं।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 18 अक्टूबर तक ऐसे 1832 स्थलों को पहले ही कवर किया जा चुका था। मंत्रालय के मुताबिक, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ऐसी कुल 28,859 फाइलों की 18 अक्टूबर तक पहले ही समीक्षा की जा चुकी है और 16,485 ऐसी फाइलों को हटाने का प्रस्ताव है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जारी अभियान के दौरान तैनात सर्वोत्तम प्रकियाओं के हिस्से के रूप में देहरादून के छावनी बोर्ड ने पॉलीथीन कचरे के निपटान के लिए देहरादून छावनी क्षेत्र में 'पॉलिथीन कचरा बैंक' शुरू किया है। पॉलीथीन अपशिष्ट यानी चिप्स रैपर, पॉलिथीन पैकिंग बैग, पॉलिथीन की बोरियां आदि लोगों से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी जाती हैं। छावनी क्षेत्र में तीन स्थलों पर पॉलीथीन कचरा बैंकों के लिए संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। एकत्र किए गए पॉलीथीन कचरे का उपयोग हाई डेनसिटी कम्पोजिट पॉलिमर (एचडीसीपी) टाइल्स, बोर्ड आदि के विनिर्माण के लिए किया जाता है। कैंट बोर्ड हर महीने न्यूनतम 70 टन से लेकर अधिकतम 100 टन पॉलिथीन कचरे की खरीद करता है।

मंत्रालय के मुताबिक, लोग अपने घर के कोने में पॉलिथीन कचरे को स्टोर कर सकते हैं और पॉलिथीन कचरे की बिक्री के लिए महीने के किसी भी दिन निकटतम 'पॉलिथीन कचरा बैंक' में जा सकते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन का कचरा घर से कचरा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को भी दिया जा सकता है।

बिहार में ट्रेन से कटकर महिला और दो बच्चों की मौत

आरा (आरएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के आरा-सासाराम रेल खंड पर शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस के मुताबिक, सेमरांव रेलवे क्रॉसिंग के समीप पटना-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो मासूम बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई। मृतकों की पहचान दुलौर टोला निवासी पिंटू सिंह की पत्नी गुडिय़ा देवी (26) और उसके पुत्र प्रियांशु और कल्लू के रूप में की गई है।

चरपोखरी के थाना प्रभारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।

मृतक के मायके वालों का आरोप है कि तीनों की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या ट्रेन से कटकर मौत का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की विभिन्न कोणों से जांच कर रही है।

दिल्ली में चलेंगी प्रीमियम बसें, हर बस में होगी वाईफाई की सुविधा

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रीमियम लग्जरी-बसों के एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे जिससे एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 बसें दिल्ली की सडक़ों पर उतार सके। ये सभी एसी बसें होंगी। कम से कम 9 सीटें होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अब इस योजना को उपराज्यपाल को भेजा गया है।

हालांकि, इस योजना को पहले ही उपराज्यपाल मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन जिस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी उस पर पब्लिक के कमेंट्स जोडऩे के बाद पहली वाली पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया है। उम्मीद है जल्द ही उपराज्यपाल इसको भी मंजूरी दे देंगे।

-इन बसों में वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी होगा।

-हर एक यात्री को सीट मिलेगी, स्टैंडिंग की परमिशन नहीं होगी।

-सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप एप से अपनी सीट बुक कर सकेंगे।

-पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिलेगी। बस रुक-रुककर नहीं जाएगी।

-जहां से आप बुक करेंगे, वहीं बस आपको पिकअप करेगी।

-चलने और पहुंचने का टाइम तय होगा।

-खास बात यह है कि प्रीमियम बसों का शुल्क डीटीसी बसों के अधिकतम किराये से ज्यादा नहीं होगा।

कनाडा आने के इच्छुक भारतीयों के लिए धीमी हो जाएगी वीजा प्रक्रिया : भारत-कनाडा विवाद के बीच बोले कनाडाई आव्रजन मंत्री

टोरंटो। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर नई दिल्ली के साथ राजनयिक विवाद के बाद ओटावा द्वारा अपने 41 राजनयिकों को निकाले जाने के बाद भारत में वीजा प्रक्रिया प्रभावित होगी। भारत के यह कहने पर कि वह राजनयिक उपस्थिति में समानता चाहता है, कनाडा ने कहा कि अब से केवल 21 कनाडाई राजनयिक और आश्रित भारत में तैनात रहेंगे।

ओटावा में विदेश मंत्री मेलानी जोली के साथ गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मिलर ने कहा कि इस कदम के परिणामस्वरूप कनाडा आने के इच्छुक भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। उन्होंने कहा, भारत सरकार के इस अस्वीकार्य और एकतरफा फैसले से प्रसंस्करण समय अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा, लेकिन हम कनाडा आने के इच्छुक लोगों पर प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे।

मिलर की टिप्पणी के बाद, आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत में उसके कर्मचारियों को 27 से घटाकर सिर्फ पांच किया जा रहा है। हालांकि, मिलर ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की कम संख्या के अल्पकालिक प्रभाव होंगे, और कनाडा सभी अस्थायी और स्थायी निवासी आवेदनों को स्वीकार करना और संसाधित करना जारी रखेगा। आईआरसीसी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर (वीएसी) के लिए काम के बोझ को समायोजित करके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, जो पहले से ही भारत से अधिकांश आवेदनों को संसाधित करते हैं, लेकिन कुछ काम ईमेल द्वारा करना होगा। कनाडाई आव्रजन निकाय ने एक बयान में कहा कि भारत से बड़ी संख्या में आवेदन पहले से ही देश के बाहर संसाधित किए गए हैं, भारत के 89 प्रतिशत आवेदन वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से संसाधित किए गए हैं। आईआरसीसी ने जारी एक बयान में कहा, कनाडा स्थित आईआरसीसी के पांच कर्मचारी, जो भारत में रहेंगे, वे उस काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके लिए तत्काल प्रसंस्करण, वीजा प्रिंटिंग, जोखिम मूल्यांकन और प्रमुख भागीदारों की देखरेख जैसी देश में उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आईआरसीसी के अनुसार, भारत के ग्राहकों को अगले कुछ महीनों में समग्र प्रसंस्करण समय, उनकी पूछताछ के जवाब और उनके वीजा या पासपोर्ट वापस मिलने में कुछ देरी हो सकती है।